

‘केंद्रीय बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम’

पीएम मोदी ने भारत की अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय नीति पर किया फोकस, परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था हुई मजबूत : राव राजेंद्र सिंह शेखावत

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर भाजपा जयपुर दक्षिण जिला की ओर से प्रबुद्धजन सम्मेलन तथा प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रबुद्धजन सम्मेलन में सांसद मंजू शर्मा और राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने तथा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बजट को सर्वे स्पर्शी, सर्व समावेशी बताया हुए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने वाला बताया। इस दौरान विधायक कैलाश वर्मा, जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने भी बजट को लेकर चर्चा की।



भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसद राव राजेंद्र सिंह ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। देश के मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के चलते आज हम विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं, और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को

‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के नेतृत्व में राजस्थान के विकास में देखने को मिली गति’

इससे भारत विकसित देशों के साथ बराबर खड़ा हो पाया है। यह देश के स्वाभिमान और स्वातंत्र्य की परिधी को परिभाषित करता है। सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने पांव मजबूत किए हैं। आज भारत नासा की तुलना में कई गुणा कम लागत पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है, ऐसे में विश्व के कई देश हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यह विश्व में हमारे मजबूत अंतरिक्ष नीति को दर्शाता है। इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में अपनी नई पॉलिसी के साथ कार्य कर रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हम विकसित भारत 2047 के सपने का साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास की गति देखने को मिल रही है। भाजपा सरकार का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है, उसकी तुलना में हम 50 फीसदी से ज्यादा पहुंच चुके हैं और अगले चार साल में इस लक्ष्य को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने प्रदेश की जनता को केंद्रित करते हुए अपने पिछले दो बजट पेश किए। इसमें किसान की आय बढ़ाने के साथ, आधारभूत व्यवस्था में निवेश, अन्नदाता के खेत से लेकर आमजन के घर तक शुद्ध जल पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। भाजपा सरकार ने यमुना, चंबल और साबरमती परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाते हुए विकसित भारत की पृष्ठभूमि में विकसित राजस्थान की व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम किया है। कार्यक्रम में जयपुर दक्षिण जिला प्रभारी विमल अग्रवाल, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, संयोजक हृदय सुमन पारीक भी मंच पर उपस्थित रहे।

करतारपुरा नाले को पक्का करने और प्रभावित मकानों को तोड़ने का मामला सदन में उठा

जयपुर। जयपुर के करतारपुरा नाले की चौड़ाई बढ़ाने और उसको पक्का करने के लिए जिन मकानों को तोड़ा जाना है, उसका मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा। मालवीय नगर क्षेत्र से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाते हुए कहा- करतारपुरा नाले की चौड़ाई 30 मीटर करने के कारण 500 मकान टूटेंगे। 500 मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं, जिससे लोगों में दहशत है।

विधायक सराफ ने कहा, “500 मकानों पर लाल निशान लगाने से लोग दहशत में हैं”

यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा, “हाईकोर्ट में रिवाइज्ड योजना पेश करेंगे”

हालत में इसे नहीं होने दिया जाएगा। हाईकोर्ट में ये निर्देश नहीं दिए कि नाले की चौड़ाई 30 मीटर की जाए। इसके दोनों तरफ 10-10 मीटर सड़क बनाने का जिम्मा है।

यूडीएच मंत्री डाक्टर सिंह खर्रा ने कहा कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 2018 में हाईकोर्ट ने नाले को पक्का करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। अब 2018 से लेकर अब तक जो हुआ उस पर कमेंट नहीं करूंगा। इस पर तोचते हुए सराफ ने कहा कि जनता को तब पता लगता है जब लाल निशान लगे।

सराफ ने कहा कि द्रव्यवती नदी में गिरने वाले नाले का 25 मीटर आउटफॉल है। कच्चे नाले की 30 मीटर चौड़ाई करने का क्या औचित्य है? लोकतंत्र में 500 मकानों को तोड़े जाना संभव नहीं है, किसी

मकान तोड़कर सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाना चाहिए। बीजेपी राज में इसके लिए अमृत योजना में 21 करोड़ मंजूर किए थे और मैंने उद्घाटन किया। सरकार बदलने के बाद कांग्रेस राज में यह कहकर इसे बंद कर दिया कि जमीन नहीं है। 30 कॉलोनियों के लोग बदनू से परेशान हैं, यहां एसटीपी बनाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर योजना में बन रहे माही अपार्टमेंट सेक्टर-23 में एमआईजी-बी के 143 एवं समृद्धि अपार्टमेंट में एमआईजी-ए के 96 प्लेटों की स्वीकृत की गई निविदाओं के साथ ही मण्डल की अन्य योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों पर स्वीकृत प्रदान की गई।

ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर कठोर कार्यवाही

जयपुर। सहकारिता विभाग में ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। रविशंकर, सहकारी समितियों मंजू राजपाल द्वारा इस सम्बन्ध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

सहकारिता विभाग ने वर्तमान गठित पैनल से हटाया, भविष्य में पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई

राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आज से

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आपर्ण अग्रणी राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान एवं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु आयुष विभाग द्वारा 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला-2025 का आयोजन 1 मार्च से 4 मार्च तक शिल्पग्राम, जवाहर कला केन्द्र में किया जाएगा।

मिशन मोड में करें नवीन आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन : गालरिया

जयपुर। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं मंडल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 250 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई।

राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 250 वीं बोर्ड बैठक

उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर योजना में बन रहे माही अपार्टमेंट सेक्टर-23 में एमआईजी-बी के 143 एवं समृद्धि अपार्टमेंट में एमआईजी-ए के 96 प्लेटों की स्वीकृत की गई निविदाओं के साथ ही मण्डल की अन्य योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों पर स्वीकृत प्रदान की गई। आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि पर वर्ष 2024-25 की अवधि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 की एवं शेष अवधि 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 की संचालक मण्डल की कार्यान्वयन स्वीकृत प्रदान की गई। गालरिया ने इस अवसर पर कहा कि मण्डल में चल रही

आदिवासियों के अलग धर्म कोड पर विधानसभा में नोकझोंक

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। विधानसभा में जनजाति विकास और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान आदिवासियों के अलग धर्म कोड के मुद्दे पर कई बार नोकझोंक और हंगामा हुआ।

जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते वे एसटी आरक्षण, टीएसपी का फायदा छोड़ें : समाराम गरसिया

बीजेपी विधायक समाराम गरसिया ने सदन में कहा, “आदिवासी का कोई धर्म कोड नहीं, वह हिंदू है।”

गणेश घोषरा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और प्राचीन समय से हिंदू धर्म से जुड़े हैं, रामायण और महाभारत में भी इसके प्रमाण मिल जायेंगे। ज्ञात रहे कि आदिवासी इलाके के कांग्रेस और बीजेपी के विधायक अलग आदिवासी धर्म कोड की पहले भी मांग करते आए हैं।

बहस में भाजपा विधायक समाराम गरसिया ने कहा कि, आदिवासी का कोई धर्म कोड नहीं, वह हिंदू है। अंग्रेज यह सब लाए, आदिवासी गर्व से कहता है कि वह हिंदू है। उन्होंने कहा- जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते वे एसटी आरक्षण और टीएसपी को लाभ छोड़ दें। उन्हें दो धर्म का लाभ थोड़े ही मिल सकता है। जो खुद हिंदू

नहीं हैं तो एसटी आरक्षण का फायदा क्यों ले। आदिवासी परंपरागत हिंदू है। उधर कांग्रेस विधायक गणेश घोषरा ने कहा कि, आदिवासियों का अलग से धर्म कोड लागू होना चाहिए। जब बौद्ध, जैन धर्म का अलग से कोड है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं है। आदिवासियों की यह मांग लंबे समय से की जा रही है। आदिवासियों को टीएसपी क्षेत्र में नौकरियों का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है।

हनुमानगढ़ जिले में गोदाम आवंटन में अनियमितता पर की है कार्यवाही : दक

जयपुर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि हनुमानगढ़ जिले में गोदाम निर्माण में पाई गई अनियमितता के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य प्रबंधक, केंद्रीय सहकारी बैंक, हनुमानगढ़ को निर्लिखित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई।

आदेश की पालना क्यों नहीं की : अदालत

जयपुर। जयपुर मेट्रो-द्वितीय को कॉमर्शियल कोर्ट-एक ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई इकाइयों से निकले अपशिष्टों के जल उपचार पर प्रबंधन के लिए बनाए सौंटीपीपी को निर्माण राशि व इससे जुड़ी करीब 96 करोड़ रुपए की वसूली मामले में आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर सहित पांचयून कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे एक मार्च को स्पष्टीकरण देकर यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने 14 फरवरी 2025 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना क्यों की और क्यों ना इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह निर्देश मैजिस्ट्रेट एडवर्ड एंथोपकर टैकनॉलॉजीज के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अर्वाड होल्डर की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि उन्होंने कोर्ट के सेल अमीन को सहयोग नहीं किया और इसके चलते ही उसने कुर्क वारंट को बिना तामील ही कोर्ट में वापस किया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए वे स्पष्टीकरण दें।

दक प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधान कार्यालय स्तर से प्रत्येक जिले में निरीक्षक दलों द्वारा निरीक्षण भी कराया गया। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन भी किया गया है।

भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं कोटा जिले में उपज के अनुपात में भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम होने से इन जिलों में भण्डारण निर्माण को प्राथमिकता देते हुए श्रीगंगानगर में 17, हनुमानगढ़ में 15 एवं कोटा में 13 गोदाम स्वीकृत किये हैं। परिणामस्वरूप इन जिलों की भण्डारण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महती योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत उन वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनमें

इससे पहले विधायक संजोय कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश की 211 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदान पर गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु कुल 3832 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में करस्टम हार्थरिंग सेंटर की स्थापना के लिए शत प्रतिशत अनुदान के स्थान पर केन्द्र सरकार से लागत के 80 प्रतिशत (अधिकतम रुपए 8 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

‘बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मार्च तक’

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोट ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक किया जायेगा।

प्रदेश में 1731 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दी रीट परीक्षा



रीट की परीक्षा खत्म हुई तो घर लौटने वालों का रैला लग गया। जयपुर जंक्शन पर जान जोखिम में डालकर अभ्यर्थी रैलागाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे।

जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2024 का आयोजन 27-28 फरवरी को सफलता पूर्वक किया गया। परीक्षा दो दिन में तीन परियों में आयोजित हुई। शुक्रवार को आयोजित परीक्षा में 88,55 प्रतिशत परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षा के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा की पारदर्शिता एवं परीक्षा की शुचितता के लिए समस्त 1731 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। रीट परीक्षा में नवांबर के तहत डमी परीक्षाएँ एवं अवांछित तत्वों पर नियंत्रण के लिए पहली बार लगभग परीक्षार्थियों के बायोमैट्रिक एवं फेस रिकग्निशन की व्यवस्था की गई। परीक्षा के दौरान सभी जिलों में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। प्रश्न पत्रों को पूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षा

मदन दिलावर ने रीट के निर्विघ्न संचालन पर हर्ष जताया है। शासन सचिव, शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने तीन साल बाद निर्विघ्न रूप से संचालित हुई रीट के लिए सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है।

केंद्रों तक पहुंचाया गया वहीं परीक्षा समाप्त के बाद ओएमआर शीट्स व परीक्षा सामग्री संग्रहण केंद्रों से रीट कार्यालय में पूर्ण सुरक्षा के साथ प्रेषित की गईं। गौरतलब है कि तीन साल बाद रीट की परीक्षा बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न हुई। शिक्षामंत्री

कुछ लोग राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक टिप्पणी से नहीं चूकते : शेखावत जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। शेखावत ने शुक्रवार जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की हिंदी के विरोध में आई प्रतिक्रिया पर शेखावत ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको पहले हिंदी के विषय में जानना चाहिए। हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। मां भारती के भाल की बिंदी है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उस पर इस तरह की टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों की भावनाओं को उकसाना गलत है।

